Financial Express, Delhi, 13/03/2026
Page No: 6, Size: 9.74cm × 7.38cm

Haryana plant production may be impacted: Somany Ceramics

SOMANY CERAMICS ON Thursday said production at its Kassar plant in Haryana may be partially impacted due to restricted gas supply following the war in West Asia. The company has received a communication from GAIL (India) stating that gas supplies to industrial consumers shall be maintained at 80% of the past six months' average gas consumption and any 'overdrawl' shall be invoiced as per the applicable contractual terms and conditions, with effect from March 12, Somany Ceramics said in a regulatory filing. **PTI**

Haryana grapples with LPG crisis as supplies dip amid West Asia conflict

UNITED NEWS OF INDIA
Chandigarh, 12 March

The escalating geopolitical tensions between the United States, Israel, and Iran have triggered a severe energy crisis in Haryana, leading to widespread disruptions in LPG distribution and the emergence of a rampant black market.

While commercial gas supplies have been effectively suspended, domestic delivery cycles have been hit hard, with consumers reporting wait times exceeding 10 days.

The scarcity has led to exorbitant pricing in the underground market, with domestic cylinders reportedly selling for up to ₹1,500 in Gurugram, while commercial units are fetching between ₹3,000 and ₹4,000.

The crisis has led to chaotic scenes at distribution centers across the state. In Hisar, an agency operator reportedly fled and locked the premises after being overwhelmed by an agitated crowd. Similarly, in Sirsa and other districts, police personnel have been deployed to manage long queues and maintain order.

The impact has reached religious institutions as well; the management of the Mansa Devi Temple in Panchkula announced that starting Friday, they will stop serving rotis in the daily 'langar' (community kitchen) for 25,000 devotees, shifting instead to a menu of pulses and rice due to the fuel shortage. In a bid to manage the dwindling stocks, the government has revised booking regulations, mandating a 25-day gap between subsequent refills for domestic users. The industrial and hospitality sectors are facing a significant slump, particularly in Murthal, Haryana's prominent food hub.

The Gas Authority of India Ltd (GAIL) has slashed piped natural gas (PNG) supplies to Murthal's dhabas by 20%. Manjeet Singh, President of the Murthal Dhaba Association, noted that while major establishments like Amrik-Sukhdev and Gulshan are currently absorbing the impact without raising food prices, a prolonged shortage could threaten the livelihoods of nearly 10,000 workers tied to over 100 eateries in the region.

Chief Minister Nayab Saini has issued a stern warning against hoarding and has authorized Deputy Commissioners to take strict action under the Essential Commodities Act and LPG Regulation Act.

To assist the public, the state government has appointed a nodal officer and launched a toll-free helpline (18001802087), although many consumers have complained that the number remained unreachable on Thursday.

Task forces have been established in most districts to monitor distribution and curb illegal trade, as the administration struggles to balance the limited supply against surging domestic demand.

Hindustan, Meerut, 13/03/2026
Page No: 6, Size: 24.77cm × 10.61cm

55 हजार लोग पीएनजी गेल गैस आपूर्ति से बेफ्रिक

पीजी गैस के लिए उपभोक्ताओं की ओर से मारामारी जैसे बनाए जा रहे हालातों के बीच गेल गैस की ओर से शहर में की जा रही पीएनजी गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से लेकर उद्यमी तक बेफ्रिक है। गेल गैस कंपनी के महाप्रंबधक विनय कुमार का कहना है कि शहर के अधिकांश इलाकों में गेल गैस की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन का नेटवर्क बिछा हुआ है। कनेक्शन के लिए डिमांड आ रही है। करीब 55 हजार उपभोक्ताओं एवं 200 इंडस्ट्री को कमर्शियल गैस की प्रतिदिन करीब सवा दो लाख एससीएमडी की आपूर्ति की जाती है।

गुरुवार को परतापुर क्षेत्र के पुट्ठा रोड स्थित गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर लगी लोगों की कतार। • हिन्दुस्तान

Janwani, Meerut, 13/03/2026
Page No: 2, Size: 30.51cm × 17.46cm

गेल कंपनी को 20 प्रतिशत कम गैस इस्तेमाल करने के निर्देश

● जनवाणी संवाददाता, मेरठ

देश भर में जहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है तो इस बीच गेल गैस ने भी अपने ग्राहको के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं और पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

गेल गैस के जीएम विनय कुमार ने बताया कि वैसे तो हमारे पास अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन माहौल देखते हुए और भविष्य में कोई परेशानी ग्राहकों को न हो इसके लिए हमने अपने कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन वाले ग्राहकों को 20 प्रतिशत गैस कम इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि गैस की सप्लाई 24 घंटे रहती है। इसलिए इस्तेमाल के मानक में पिछले 6 महीने का इस्तेमाल मुख्य रहेगा। यदि ग्राहक का पिछले छह महीनों का औसत से आने वाले महीने का बिल 20 प्रतिशत कम नहीं रहता तो ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा। विनय कुमार ने बताया कि घरेलू कनेक्शन पर अभी इसका कोई असर नहीं है। सामान्य रूप से ही सप्लाई की जा रही है। इसके साथ जब से एलपीजी की किल्लत हुई है तब से हमारे पास नए कनेक्शन के लिए भी आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। गेल गैस के लगभग 55000 कनेक्शन घरेलू और 200 से अधिक कनेक्शन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं। ऐसे में एक बड़ा वर्ग गेल गैस के भरोसे भी है। अगर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल की तरह ही घरेलू गैस पर भी जुर्माने का प्रावधान आ जाता है तो शहर में गैस को लेकर और भी ज्यादा समस्या हो सकती है।

गैस की कालाबाजारी करने वालों पर जेल जाएंगे: एसपी सिटी

गैस की कालाबाजारी करने वालों पर एसएसपी ने सीधा मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कई स्थानों पर कालाबाजारी की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। पर सूचना पहले ही लीक होने पर आरोपित फरार हो गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि रेलवे रोड और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गैस कालाबाजारी की सूचना मिली थी। पुलिस की ड्यूटी में बनाकर दोनों स्थानों पर दबिश डाली गई। सूचना लीक होने पर वहां कुछ बरामद नहीं हो पाया है। एसपी सिटी ने बताया कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले पांच नाम चिन्हित किए हैं। जिनकी निगरानी भी की जा रही है। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि गैस की कालाबाजारी की कोई जानकारी मिले। उनके और संबंधित थाने के मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं।

कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने से शादी सीजन पर संकट

● जनवाणी संवाददाता, मेरठ

शादियों का सीजन सिर पर है लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की अचानक बढ़ी कीमतों और बाजार में कमी ने होटल इंडस्ट्री और कैटर्स की चिंता बढ़ा दी है। शहर में 450 मंडप, 350 होटल और करीब 250 ढाबे संचालित होते हैं। जहां रोजाना बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत होती है। होटल इंडस्ट्री में एक होटल में प्रतिदिन औसतन 4 से 5 सिलेंडर इस्तेमाल हो जाते हैं। जबकि एक बड़ी शादी में खाना बनाने के लिए करीब 15 से 20 सिलेंडर तक की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर होटल और कैटर्स अपने पास 15 से 20 सिलेंडर का स्टॉक रखते हैं। जो अधिकतम 2 से 3 दिन तक ही चलता है।

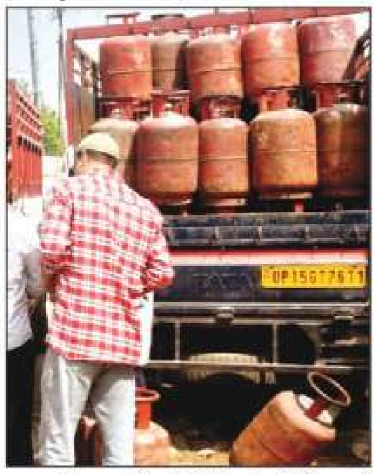

15 मार्च से शहर में शादियों का भारी साया शुरू होने वाला है। ऐसे में शादी वाले परिवारों के साथ-साथ होटल संचालक और हलवाई भी चिंता में हैं। अधिकांश जगहों पर बुकिंग और खाने मेन्यू पहले से तय हैं। लेकिन गैस सिलेंडर की कमी के कारण खाना बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। होटल संचालकों का कहना है कई ग्राहक दबाव बना रहे हैं उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है इसलिए सिलेंडर की व्यवस्था करना होटल या कैटर्स की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर हलवाइयों को भी शादी से पहले मिठाइयों और अन्य पकवानों की तैयारी के लिए लगातार गैस की जरूरत होती है। लेकिन बाजार में सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं। और जो मिल भी रहे हैं उनकी कीमत सामान्य से तीन गुना तक बताई जा रही है। इसका असर होटल और ढाबों की रोजमर्रा की रसोई पर भी पड़ने लगा है और कई जगहों पर गैस की कमी के कारण मेन्यू तक सीमित करना पड़ा है। शहर में होटल और केटरिंग इंडस्ट्री से प्रतिदिन करीब 5 से 6 करोड़ रुपये का कारोबार होता है लेकिन यदि गैस संकट जल्द दूर नहीं हुआ तो यह बड़ा कारोबार प्रभावित हो सकता है।विपुल सिंघल ने बताया कि शादी समारोह और बड़े आयोजनों में गैस की काफी जरूरत होती है लेकिन इस समय सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे। अगर यही स्थिति रही तो मजबूरन शादियों में केवल दाल-रोटी और सब्जी जैसे सीमित मेन्यू ही रखने पड़ सकते हैं। प्रशासन को इस समस्या पर जल्द कदम उठाना चाहिए। खेमा हलवाई एंड कैटर्स के आकाश ने बताया कि इस समय शादी-विवाह का सीजन चल रहा है और बुकिंग पूरी तरह भरी हुई है। ऐसे में गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है जो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह प्रभावित कर रही है। समझ नहीं आ रहा कहां से भाजी के डिब्बे तैयार करें और कहां से शादी-विवाह के लिए खाना बनाएं। होटल हारमनी के निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि गैस सिलेंडर की किल्लत ऐसे ही बनी रही तो होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा और मजबूरन होटल बंद करने की स्थिति बन सकती है। इन दिनों होटल में लगातार पार्टियां और शादी समारोह बुक हैं जिनमें खाना बनाने के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।

Deshbandhu, Delhi, 13/03/2026

Page No: 10, Size: 26.19cm × 12.70cm

खाड़ी संकट का असर

गेल ने येलाहांका पावर प्लांट को गैस सप्लाई रोकी

- बिजली उत्पादन हो सकता है प्रभावित
- ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने की पुष्टि

बेंगलुरु, 12 मार्च (एजेंसियां)। सरकारी महारत्न कंपनी गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआईएल) ने गुरुवार को सुबह 6 बजे से बेंगलुरु के येलाहांका गैस आधारित पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा स्थापित 370 मेगावाट क्षमता वाला येलाहांका पावर प्लांट राज्य का एकमात्र गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र है। अधिकारियों ने बताया कि गैस सप्लाई रुकने से इसके बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

यह पावर प्लांट मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर को बिजली आपूर्ति के लिए बनाया गया था, और यह पिछले साल दिसम्बर से लगातार काम कर रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पैदा हुई प्राकृतिक गैस की कमी से अब यहां बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण देश भर में गैस की कमी हो गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने गैस आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की है। इससे कर्नाटक में बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट के कारण देश

भर में एलपीजी और प्राकृतिक गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्राकृतिक गैस के आवंटन में प्राथमिकता तय की है। इस सूची में घरेलू खपत को सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि परिवहन और उर्वरक (फर्टिलाइजर) क्षेत्र को अगली प्राथमिकता दी गई है। वहीं, बिजली उत्पादन क्षेत्र को सबसे निचली प्राथमिकता में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली की अधिक मांग के दौरान आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार सभी उपलब्ध स्रोतों से बिजली उत्पादन कर रही है।

वर्तमान में कर्नाटक में प्रतिदिन करीब 35.5 करोड़ यूनिट बिजली की मांग है, जिसे थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट, सौर और पवन ऊर्जा तथा केंद्रीय ग्रिड से मिलने वाली बिजली के जरिए पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ पावर एक्सचेंज व्यवस्था के जरिए भी कुछ बिजली हासिल कर रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अगर येलाहांका पावर प्लांट को गैस सप्लाई और कम हुई, तो बिजली आपूर्ति में हल्की बाधा आ सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के तहत केंद्र सरकार ने मौजूदा एलपीजी संकट से निपटने के लिए गैस आवंटन के लिए प्राथमिक क्षेत्र तय किए हैं।

इसमें घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी), एलपीजी उत्पादन, परिवहन के लिए सीएनजी और पाइपलाइन संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत का 100 प्रतिशत गैस आवंटन मिलेगा।

कच्चा तेल फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार

मुंबई। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने का असर कच्चे तेल पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है और गुरुवार को कीमत फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड का दाम 9 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 100.76 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम करीब 9 प्रतिशत बढ़कर 95 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

कच्चे तेल में तेजी ऐसे समय पर देखने को मिली है, जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) कीमतों में तेजी को कम करने के लिए इमरजेंसी

रिजर्व से कच्चा तेल जारी करने का ऐलान कर चुका है। बीते बुधवार को 32 देशों के सदस्यता वाले आईईए ने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने का ऐलान किया है, यह अब तक के इतिहास में आईईए द्वारा कच्चा तेल जारी करने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अलग से घोषणा की कि वह रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा, और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा कि शिपमेंट अगले सप्ताह शुरू हो सकता है और इसे पूरा होने में लगभग 120 दिन लगेंगे। इससे पहले मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने के चलते कच्चा तेल 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि, बाद में गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया था।

भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यातक : एमईए

- पड़ोसी देश डीजल के लिए कर रहे अनुरोध

नई दिल्ली, 12 मार्च (एजेंसियां)। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत से उसके पड़ोसी देशों ने खास गुजारिश की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ने डीजल आपूर्ति का अनुरोध भारत से किया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। जायसवाल ने कहा कि भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, विशेषकर अपने पड़ोसियों के लिए—जैसे बांग्लादेश सरकार से डीजल आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश से भारत के पुराने रिश्तों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनके साथ हमारे जन-केंद्रित और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए, 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से हम विभिन्न माध्यमों—जैसे जलमार्ग, रेलमार्ग, और बाद में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन—से डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच हाई-स्पीड डीजल आपूर्ति को लेकर एक समग्र बिक्री-खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह 2007 से जारी है। उन्होंने कहा कि हमें मालदीव और श्रीलंका से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है।